

गौरव हरियाणा

राजनीति

मानसून सत्र से पहले मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की उम्मीद

केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, रिपोर्टों से पता चलता है कि बदलाव आगामी संसद के मानसून सत्र से पहले लागू किए जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण फेरबदल पर विचार कर रही है। इस फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल के विस्तार या फेरबदल की योजना संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही लागू की जा सकती है। इस तरह के कदम को अक्सर सरकार के कामकाज में नई ऊर्जा और रणनीतिक दिशा देने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। हालांकि, परिवर्तनों के दायरे या प्रभावित होने वाले मंत्रियों के बारे में विशिष्ट विवरण अभी तक अपुष्ट हैं, लेकिन समय-सारणी आगामी नीतिगत प्राथमिकताओं और शासन उद्देश्यों के साथ टीम को संरेखित करने के एक रणनीतिक कदम का संकेत देती है।

स्रोत: The Economic Times



चित्र: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office

शिक्षा

सोनाम वांगचुक परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे



चित्र: Wikimedia Commons / Sonam Wangchuk

प्रसिद्ध नवप्रवर्तक और शिक्षा सुधार के पैरोकार सोनाम वांगचुक ने सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यह विरोध विशेष रूप से परीक्षा प्रणाली के भीतर कथित अनियमितताओं को लक्षित कर रहा है। वांगचुक का अनिश्चितकालीन उपवास रखने का निर्णय उन मुद्दों की गंभीरता को दर्शाता है जिन्हें वे और CJP उठा रहे हैं। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट में विशिष्ट परीक्षाओं और कथित अनियमितताओं की प्रकृति का विवरण नहीं दिया गया है, यह कदम निष्पक्षता और अखंडता के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की निष्पक्षता और अखंडता के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए अधिकारियों पर सार्वजनिक ध्यान और दबाव लाने का लक्ष्य रखता है। वांगचुक की भागीदारी और भूख हड़ताल से अब मजबूत हुए इस विरोध का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की निष्पक्षता और अखंडता के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए अधिकारियों पर सार्वजनिक ध्यान और दबाव लाना है।

स्रोत: The Economic Times

चित्र: Wikimedia Commons / Amol.Gaitonde

अपराध

हरियाणा आईडीएफसी धोखाधड़ी: निलंबित आईएएस अधिकारी ने पूर्व HSPCB प्रमुख को घेरा

हरियाणा के एक निलंबित आईएएस अधिकारी ने कथित आईडीएफसी धोखाधड़ी मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया है। जमानत याचिका में, अधिकारी ने कथित तौर पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के पूर्व अध्यक्ष को फंसाया है। कथित धोखाधड़ी का विवरण और अधिकारियों को सौंपी गई विशिष्ट भूमिकाएं चल रही जांच का हिस्सा हैं। पूर्व एचएसपीसीबी प्रमुख का नाम लेने के लिए निलंबित अधिकारी की चाल इस मामले में जांच के संभावित विस्तार का संकेत देती है। अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका और उसमें लगाए गए आरोपों पर विचार कि...

स्रोत: ThePrint

शिक्षा

केंद्र ने NIT कुरुक्षेत्र के निदेशक के अधिकार वापस लिए



केंद्र सरकार ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) के निदेशक को सौंपे गए प्रमुख प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार आधिकारिक तौर पर वापस ले लिए हैं। यह निर्णय संस्थान के नेतृत्व की परिचालन शक्ति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इन अधिकारों को वापस लेने के पीछे के विशिष्ट कारणों का प्रारंभिक रिपोर्टों में विवरण नहीं दिया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के कदम आम तौर पर सार्वजनिक धन से वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर निरीक्षण और शासन संबंधी विवादों से जुड़े होते हैं। NIT कुरुक्षेत्र में दिन-प्रतिदिन के कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर आगे के प्रभावों को अभ...

स्रोत: The News Mill

विज्ञापन

बंदिनी
इरादों की एक कालजयी यात्रा
डॉ. राजश्री वर्मा

प्रेरणादायक
किताब पढ़ना चाहते हैं?

बंदिनी
इरादों की एक कालजयी यात्रा

डॉ. राजश्री वर्मा

ORDER YOUR COPY TODAY
www.vermaverse.com

8409170482
* AVAILABLE ONLINE *

प्रेरणा

आत्मविश्वास

संघर्ष

सफलता

एक महिला के संघर्ष,
साहस और सफलता
की प्रेरक कहानी

विज्ञापन

बिल्डर की देरी पर हरियाणा RERA का 26 लाख का मुआवजा आदेश

हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने एक बिल्डर को एक घर खरीदार को 26 लाख रुपये का भारी मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश डेवलपर द्वारा तय समय-सीमा के भीतर संपत्ति की डिलीवरी करने में विफलता के कारण खरीदार को हुए वित्तीय नुकसान को संतुष्ट करता है। प्राधिकरण के इस फैसले में प्रोजेक्ट में देरी के कारण घर खरीदारों पर पड़ने वाले प्रभाव को स्वीकार किया गया है, खासकर ऐसे बाजार में जहां प्रॉपर्टी की कीमतों में...

स्रोत: The Economic Times